1 अप्रैल, 2025

प्रती,

श्री चंद्रशेखर बवनकुले
अध्यक्ष,
महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक 2024 पर बनी संयुक्त चयन समिति
महाराष्ट्र विधान सभा
ईमेल: cbawankule.in@gmail.com , cbawanbkule@gmail.com

विषयः महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, 2024 के संबंध में आपत्तियां और चिंताएं।

आदरणीय सर,

हम, न्याय और शांति के लिए नागरिक (सिटिझन्स फॉर जस्टिस अँड पीस , मुंबई), महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, 2024 (इसके बाद एमएसपीएस विधेयक 2024) जिसे, 18 दिसंबर, 2024 को राज्य विधानसभा में फिर से पेश किया गया था,पर अपनी गहरी चिंताओं और मज़बूत आपत्तियों को व्यक्त करने के लिए लिख रहे है ।विधेयक की जांच करने और विधानसभा सत्र में अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए 21 सदस्यीय संयुक्त चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में, हम आपसे महाराष्ट्र में नागरिक स्वतंत्रता के लिए इस क़ानून के गंभीर प्रभावों पर विचार करने का आग्रह करते हैं, विशेष रूप से भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ और विधानसभा, शांतिपूर्ण विरोध और गोपनीयता के मौलिक अधिकारों पर इसके संभावित प्रभाव पर विचार करते हैं।

विधेयक को शुरू में 11 जुलाई, 2024 को तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा पेश किया गया था, जिनके पास पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार की ओर से गृह, क़ानून और न्यायपालिका विभाग भी थे। हालांकि, यह विधानसभा के कार्यकाल के समापन के साथ समाप्त हो गया। दिसंबर 2024 में इसके पुन: परिचय को, पारदर्शिता की परेशान करने वाली कमी से चिह्नित किया गया है। विधेयक को सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं कराया गया है, न ही इसे किसी भी प्रकार के सार्वजनिक परामर्श या जांच के अधीन किया गया है। इसके बजाय, इसे सार्वजनिक चर्चा के लिए प्रसारित किए बिना सीधे संयुक्त चयन समिति को भेजा गया था। हम इस अपारदर्शी विधायी प्रक्रिया का कड़ा विरोध करते हैं। इस तरह के महत्व का क़ानून, नागरिक स्वतंत्रता के लिए दूरगामी परिणामों के साथ, विधायिका द्वारा विचार किए जाने से पहले कठोर सार्वजनिक बहस के लिए खुला होना चाहिए।

इसके अलावा, विधेयक पेश करते समय विधानसभा में दिए गए बयानों ने हमारी आशंकाओं को और गहरा कर दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस आधार पर विधेयक को उचित ठहराया कि यह महाराष्ट्र में "शहरी नक्सलवाद" का मुकाबला करने और शहरी स्थानों में "फ्रंटल संगठनों" की गतिविधियों पर अंकुश लगाने का प्रयास करता है जो कथित तौर पर देश और उसके संस्थानों के बारे में "अविश्वास" पैदा करते हैं। हम इस तर्क को अत्यधिक समस्याग्रस्त पाते हैं, क्योंकि "अविश्वास" की धारणा अस्पष्ट और व्यक्तिपरक दोनों है, जिसमें किसी भी स्पष्ट क़ानूनी परिभाषा का अभाव है। सरकारी नीतियों की आलोचना करने और संस्थागत जवाबदेही की मांग करने का वैध अधिकार - लोकतांत्रिक जुड़ाव का एक अनिवार्य हिस्सा - को आसानी से "अविश्वास" को बढ़ावा देने और नागरिकों, कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार रक्षकों के ख़िलाफ़ हथियार बनाने के रूप में ग़लत समझा जा सकता है। यदि जनता का एक वर्ग राज्य या उसके संस्थानों के बारे में संदेह रखता है, तो यह सरकार की ज़िम्मेदारी है कि वह पारदर्शिता और जवाबदेही के माध्यम से उनकी चिंताओं को दूर करे, न कि उन्हें अपराधी बनाकर।

विडंबना यह है कि, जबकि एक पूरे क़ानून को एक शब्द का उपयोग करके तैयार करने की मांग की जा रही है, शहरी नक्सलियों (ख़तरे) को आवश्यकता और आधार के रूप में, गृह मंत्रालय ने 2022 में, और पहले स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार "शहरी नक्सल" शब्द का उपयोग नहीं करती है जब यह वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) की बात आती है, "शहरी क्षेत्रों में हो या किसी अन्य स्थान पर, एक सतर्कता रखी जाती है और सख़्त कार्रवाई शुरू की जाती है।
(https://www.mha.gov.in/MHA1/Par2017/pdfs/par2020-pdfs/rs-11032020/1978.pdf)

"शहरी नक्सलवाद" से निपटने के नाम पर - जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, एक विवादास्पद शब्द जिसका वास्तव में कोई आधार नहीं है या क़ानून - हम समझते हैं कि यह विधेयक, वास्तव में, असंतोष को दबाने और नागरिकों, कलाकारों और अन्य लोगों की स्वतंत्र आवाज़ों को लक्षित करने के लिए तैनात किया जाएगा, जो राज्य की नीतियों को चुनौती देते हैं या अन्याय को उजागर करते हैं। इसके अस्पष्ट और व्यापक प्रावधान (परिभाषाएं) व्यापक दुरुपयोग की संभावना पैदा करते हैं, जिससे राजनीतिक विरोधियों, पत्रकारों, नागरिक समाज संगठनों और मानवाधिकार रक्षकों के अपराधीकरण का द्वार खुल जाता है। यह गंभीर संवैधानिक चिंताओं को उठाता है, क्योंकि विधेयक भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों के साथ सीधे संघर्ष में प्रतीत होता है।

इस तरह के क़ानून को लाने के पीछे औचित्य यह है कि सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के समान संस्करण वर्तमान में छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में लागू हैं। एक और तर्क जो एमएसपीएस विधेयक 2024 में लाने की पेशकश की जा रही है वह यह है कि यह व्यक्तियों और संगठनों की कुछ ग़ैरक़ानूनी गतिविधियों की अधिक प्रभावी रोकथाम प्रदान करेगा। हालांकि, महाराष्ट्र राज्य में पहले से ही महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (एमसीओसीए, 1999) है, जिसके तहत कई अपमानजनक अभियोजन शुरू किए गए हैं।

जबकि प्रक्रियाएं विवादास्पद यूएपीए, 1961 [(अवैध गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम] के समान हैं, विधेयक ग़ैरक़ानूनी गतिविधि की अपनी परिभाषा का विस्तार करता है, "सार्वजनिक व्यवस्था के लिए ख़तरा होने" और "क़ानून के प्रशासन में हस्तक्षेप करने" से लेकर "जनता में भय और आशंका पैदा करना" और "क़ानून की अवज्ञा का प्रचार करना" सब कुछ अपने दायरे में लाता है। हालांकि, नए लागू भारतीय न्याय संहिता के साथ, 2023 में "आतंकवादी गतिविधियां" (धारा 113), "संगठित अपराध" (धारा 111) और "तुच्छ संगठित अपराध" (धारा 112) जैसे अपराधों को देश को नियंत्रित करने वाले आपराधिक क़ानूनों में लाने के साथ, एक अलग एमएसपीएस विधेयक की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। बीएनएस के माध्यम से, ग़ैरक़ानूनी गतिविधि (रोकथाम)

अधिनियम, 1961 और एमसीओसीए के प्रावधानों को पहले ही केंद्रीकृत कर दिया गया है, जिससे एक राज्य और पुलिस की भूमि में अपने स्वयं के नागरिकों के ख़िलाफ़ उपयोग करने के लिए कई उपकरण सुनिश्चित किए जा रहे हैं, जिससे उक्त विधेयक को लाने की आवश्यकता पर सवाल उठते हैं।

बिल में यह भी कहा गया है कि एक 'ग़ैरक़ानूनी संगठन का एक सदस्य ऐसे किसी भी संगठन की बैठकों या गतिविधियों में भाग लेता है या योगदान देता है या किसी भी योगदान को प्राप्त करता है या मांगता है, उसे एक अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी जो तीन साल तक हो सकती है और 3 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

इस क़ानून के महत्व और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के लिए संभावित नुक़सान को देखते हुए, हम आपकी समिति से एक पारदर्शी और समावेशी प्रक्रिया सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं जो आगे कोई कदम उठाने से पहले सार्थक सार्वजनिक जुड़ाव की अनुमति देता है। हम सम्मानपूर्वक आपके विचार के लिए अपनी आपत्तियां और सिफारिशें इस उम्मीद में प्रस्तुत करते हैं कि उचित विचार-विमर्श से एक क़ानून पारित होने से रोका जा सकता है जो महाराष्ट्र और भारत के मूल लोकतांत्रिक मूल्यों को ख़तरा है।

न्याय और शांति के लिए नागरिक, मुंबई, विशेषज्ञों और अधिवक्ताओं के परामर्श से, विधेयक के विशेष प्रावधानों से संबंधित निम्नलिखित विस्तृत आपत्तियां प्रदान करना चाहता है।

(MSPS) एमएसपीएस 2024 के समस्याग्रस्त प्रावधान

2024 के एमएसपीएस विधेयक के मसौदे में "एक ग़ैरक़ानूनी गतिविधि" ((धारा (2) (एफ) (i) से (vii)) की बेहद अस्पष्ट, व्यापक और इसलिए समस्याग्रस्त परिभाषाएं हैं। यह ढीली परिभाषा दुर्भावनापूर्ण दुरुपयोग के लिए उत्तरदायी है। उदाहरण के लिए, ((धारा (2) (f) (i)) वाक्यांश की व्याख्या ... "जो सार्वजनिक व्यवस्था, शांति और शांति के लिए ख़तरा या ख़तरा है" को संभावित दुरुपयोग के साथ व्याख्या के लिए खुला छोड़ दिया गया है। परिभाषा में "ख़तरा" शब्द का उपयोग अपने आप में समस्याग्रस्त है क्योंकि "ख़तरा" शब्द को क़ानून में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। यह उजागर करना महत्वपूर्ण है कि शब्द का शब्दकोश अर्थ है, व्यक्ति का ख़तरनाक कार्य, और इसे अधिकारियों के लिए खुला छोड़ देता है ताकि वे अपने विवेक के अनुसार अधिनियम के तहत कुछ भी ला सकें और लक्षित लोगों को दंडित कर सकें। (वे कह सकते हैं कि सड़कों पर खाना बनाना जनता के लिए ख़तरा है और लोगों को गिरफ़्तार करना है)।

आपराधिक कृत्यों के रूप में अपरिभाषित "कार्यों" को बनाने और शामिल करने के लिए परिभाषाओं की यह अस्पष्टता बेहद समस्याग्रस्त है। किसी भी क़ानून में, किसी भी आपराधिक कार्य को अच्छी तरह से परिभाषित किया जाना चाहिए और पुलिस द्वारा शिथिल व्याख्या करने के लिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए। दुर्भाग्य से, या बल्कि सचेत रूप से, जवाबदेही से दूर होने के लिए इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया है।

इसके अलावा, धारा 2(एफ) के तहत आपराधिक कृत्य की परिभाषा अवैध गतिविधि का वर्णन इस प्रकार करती है:

(*f*) "unlawful activity" means any action taken by an individual or organization whether by committing an act or by words either spoken or written or by signs or by visible representation or otherwise,–

(*i*) which constitute a danger or menace to public order, peace and tranquility; or

(*ii*) which interferes or tends to interfere with maintenance of public order; or

(*iii*) which interferes or tends to interfere with the administration of law or its established institutions and personnel; or

(*iv*) which is designed to overawe by criminal force or show of criminal force or otherwise to any public servant including the Forces of the State Government or the Central Government in exercise of the lawful powers of such public servant and Forces; or

(*v*) of indulging in or propagating, acts of violence, vandalism or other acts generating fear and apprehension in the public, or indulging in or encouraging, the use of firearms, explosives or other devices or disrupting communications by rail, road, air or water; or

(*vi*) of encouraging or preaching disobedience to established law and its institutions; or

(*vii*) of collecting money or goods to carry out any one or more of the unlawful activities mentioned above;

जैसा कि ऊपर दी गई परिभाषा में देखा जा सकता है, कोई ठोस क्षेत्र प्रदान नहीं किया गया है, और केवल अस्पष्ट शब्दों का उपयोग उन कृत्यों की प्रकृति को परिभाषित करने के लिए किया जाता है जिन्हें अधिकारियों द्वारा ग़ैरक़ानूनी गतिविधियों के रूप में समझा जा सकता है। क़ानून पुलिस को मनमानी शक्तियां देता है और यह एक खुला रहस्य है कि सत्ता में राजनीतिक दल कई बार पुलिस अधिकार का दुरुपयोग कर रहा है।

Constitution of Advisory Board.

5. (*1*) The State Government shall constitute, as and when necessary, an Advisory Board for the purposes of this Act.

(2) The Advisory Board shall, consist of three persons who are or have been or qualified to be appointed as judge of the High Court. The Government shall appoint the members and designate one of them as the Chairperson.

(3) The term and other conditions of service of the Chairperson and members shall be such as may be prescribed.

कुछ विशेष क़ानूनों के साथ-साथ राज्य विधानों के अनुरूप, एमएसपीएस विधेयक 2024 की धारा 5(1) (2) राज्य सरकार, पुलिस और प्रशासन के कार्यों पर निर्णय लेने के लिए अधिनियम के तहत स्थापित "सलाहकार बोर्ड" की स्थापना के लिए प्रदान करती है। उत्सुकता से, उक्त प्रावधान के अनुसार, सलाहकार बोर्ड में "तीन व्यक्ति हैं, हैं, या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य हैं", जिसका अर्थ है कि - न्यायाधीशों या न्यायिक अधिकारियों के बजाय पिछले क़ानूनों/क़ानून में आपराधिक कृत्यों का मुकाबला करने के लिए अधिनियमित किया गया है --- मौजूदा सेवानिवृत्त या "ग़ैर नियुक्त अधिकारी या वकील" भी सलाहकार बोर्ड का हिस्सा बनने के लिए नियुक्त होने के योग्य हैं। चूंकि सलाहकार बोर्ड का गठन राज्य सरकार द्वारा ही किया जाना है, इसलिए किसी को उन तरीक़ों के बारे में सोचने के लिए कल्पना का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है जिनमें उक्त प्रावधान का उपयोग किया जा सकता है (या दुरुपयोग किया जा सकता है)। यह अत्यधिक संभावना है कि, न्यायिक और संवैधानिक जांच में प्रशिक्षित स्वायत्त और स्वतंत्र व्यक्तियों के बजाय, ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है

9. (*1*) Where an organization has been declared unlawful organization under section 3, the District Magistrate or the Commissioner of Police, as the case may be, within their respective jurisdiction, may notify any place which in his opinion is used for the activities of such unlawful organization. Powers to notify and take possession of places used for purpose of unlawful activities.

Explanation.–For the purpose of this section, place includes a house or a building or part thereof or a tent or a vessel.

(*2*) When any place is notified under sub-section (*1*), the District Magistrate or the Commissioner of Police or any officer authorized in this behalf in writing by him may take possession of notified place and evict therefrom any person found therein and the District Magistrate or the Commissioner of Police shall forthwith make a report of taking of possession to the Government :

Provided that, where any such place contains any apartment occupied by women or children, reasonable time and facilities shall be provided for their withdrawal with least possible inconvenience.

(*3*) A notified place whereof possession is taken under sub-section (*2*) shall remain in possession of the Government, as long as the notification issued under section 3 is in force or such earlier period as the Government decides.

जो सत्ता में किसी भी सरकार के साथ गठबंधन किया जा सकता है, या यहां तक कि कठपुतली भी हो सकता है।

धारा **9,** उप-धारा 1 के माध्यम से, प्रशासन और पुलिस (डीएम या पुलिस आयुक्त) को किसी भी अधिसूचित क्षेत्र पर क़ब्ज़ा करने या उस परिसर से बेदख़ल करने वाले व्यक्तियों को ज़ब्त करने के लिए कठोर और मनमानी शक्तियां प्रदान करती है (यदि महिलाएं और बच्चे वहां रहते हैं "उचित समय" उन्हें दी जाने वाली एकमात्र सुरक्षा है!)। इसके अलावा, धारा 10 (1) इस ज़ब्त की गई संपत्ति के भीतर चल संपत्ति, धन आदि को ज़ब्त करने के लिए इस मनमाने शक्ति का विस्तार करती है, जिससे यह एक और शक्ति मनमाने उपयोग के लिए दी जाती है।

Revision.

12. (*1*) A revision petition may be filed before the High Court against any order passed by the Government, under sub-section (*1*) of section 7 confirming the notification issued under sub-section (*1*) of section 3 or against any order passed under sub-section (*5*) of section 3 extending the period of notification or against any order of forfeiture under sub-section (*1*) of section 11, questioning the legality, correctness or propriety thereof.

(*2*) A revision petition under this section shall be filed within a period of thirty days from the date of receipt of any order referred to in sub-section (*1*).

चौंकाने वाली बात यह है कि एमएसपीएस विधेयक, 2024 के मसौदे की धारा 12 इस विवादास्पद क़ानून के तहत गिरफ़्तार किए गए लोगों को जिला स्तर पर क़ानून के किसी भी सहारा से इनकार करती है, और इस क़ानून के ख़िलाफ़ कार्रवाई को चुनौती देने के लिए कोई याचिका दायर करने के लिए उचित मंच के रूप में केवल उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को अनिवार्य करती है। यह भारतीय संविधान में निर्धारित न्याय निवारण की चार-स्तरीय प्रणाली के ख़िलाफ़ है। इसके पीछे के तर्क को स्पष्ट किया जाना बाकी है।

Bar of jurisdiction.

14. Save as otherwise expressly provided in this Act, and without prejudice to the jurisdiction and powers of the Supreme Court and the High Court under the Constitution of India, no proceeding taken under this Act by the Government or the District Magistrate or the Commissioner of Police, or any officer authorized in this behalf by the Government or the District

9

Magistrate or the Commissioner of Police, shall be called in question in any court in any suit or proceeding or application or by way of appeal or revision and no injunction shall be granted by any court or other authority in respect of any action taken or to be taken in pursuance of any power conferred by or under this Act.

Protection of action taken in good faith.

15. No civil or criminal proceeding shall be instituted against any person for anything done in good faith or intended to be done under this Act or against the Government or any person acting on behalf of or by the authority of the Government, for any loss or damage caused to or in respect of any property, whereof possession has been taken by the Government under this Act.

एमएसपीएस विधेयक 2024 की विवादास्पद धारा 14 और 15 के तहत, प्रत्येक पुलिस अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट (नौकरशाह) को किसी भी प्रतिबंध के लिए दंडित या जवाबदेह ठहराए जाने से सुरक्षा प्रदान की गई है जो प्रस्तावित क़ानून के तहत अभियोजन के दुरुपयोग पर उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित किया जा सकता है। ये धाराएं क़ानून को दुरुपयोग के लिए खुला रखती हैं क्योंकि स्पष्ट रूप से ग़लत आवेदन या दुरुपयोग के लिए कोई दंड नहीं है, क्योंकि उक्त दो धाराओं में कहा गया है कि ऐसे अधिकारियों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती है।

मौजूदा बीएनएस, 2023, यूएपीए, 1967 और पीएमएलए, 2002 के सामने नए बिल (एमएसपीएस अधिनियम) के ख़तरे

प्रस्तावित क़ानून, एमएसपीपी विधेयक 2024, को निम्नलिखित के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए:

एमएसपीपी बिल 2024 का बीएनएस 2023 और यूएपीए 1961 जैसे मौजूदा क़ानून के प्रकाश में गंभीर रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए, जो पहले से ही 'आतंकवादी या अलगाववादी' मानी जाने वाली गतिविधियों को संबोधित करने के लिए व्यापक क़ानूनी ढांचा प्रदान करते हैं। ये क़ानून राज्य को राष्ट्रीय सुरक्षा, अखंडता या संप्रभुता के लिए ख़तरा पैदा करने वाले कृत्यों में शामिल व्यक्तियों के ख़िलाफ़ कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण शक्तियां प्रदान करते हैं।

एमएसपीपी विधेयक की शुरूआत, अपने व्यापक और अस्पष्ट प्रावधानों के साथ, अनावश्यक अतिवृद्धि के बारे में चिंताओं को बढ़ाती है, क्योंकि इन मुद्दों को पहले से ही यूएपीए और बीएनएस द्वारा पर्याप्त रूप से संबोधित किया गया है। एक अतिरिक्त क़ानून का निर्माण, विशेष रूप से एक जो राजद्रोह और आतंकवाद के प्रावधानों का विस्तार

करता प्रतीत होता है, मनमाने राज्य कार्रवाई के ख़िलाफ़ मौलिक स्वतंत्रता और न्यायिक सुरक्षा उपायों को और नष्ट करके संवैधानिकता की भावना को कमजोर करता प्रतीत होता है।

सबसे गंभीरता से, यह उन व्यक्तियों और संगठनों के उत्पीड़न द्वारा मौलिक अधिकारों के खुले दुरुपयोग और इनकार को प्रस्तुत करता है जो क़ानून के आरोपों की बहुलता के तहत उत्पीड़न के क़ानूनी और संवैधानिक रूप से कार्य करते हैं।

धारा 152 सहित बीएनएस, 2023 में विभिन्न खंड, जो आईपीसी 124-ए के तहत 'राजद्रोह' को फिर से पेश करता है और विशेषज्ञों द्वारा 'राजद्रोह प्लस' के रूप में वर्णित किया गया है, धारा 113, जो अस्पष्ट रूप से आतंकवादी कृत्यों के रूप में परिभाषित कृत्यों को अपराधी बनाता है, और धारा 111, जो संगठित अपराधों को लाती है, अधिकारियों को उन व्यक्तियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए मनमाने अधिकार देती है जो राष्ट्रीय अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के ख़िलाफ़ माने जाने वाले कार्य करते हैं। फिर से यहां, बीएनएस 2023 में 'राष्ट्रीय अखंडता' और 'राष्ट्रीय सुरक्षा' की परिभाषाएं मौलिक रूप से समस्याग्रस्त हैं क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई अवसरों पर पूर्व भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124-ए के तहत मूल 'देशद्रोह अनुभाग' के आवेदन को इस आधार पर ख़ारिज कर दिया है कि यह केवल हिंसा का कार्य है जो विशेष रूप से इस कठोर खंड के संभावित उपयोग को वैध बनाता है। वास्तव में माननीय उच्चतम न्यायालय ने राय व्यक्त की है कि इस तरह के एक खंड को एक कार्यशील लोकतंत्र की क़ानून पुस्तकों में कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। दुर्भाग्य से, इस विकसित न्यायशास्त्र का सम्मान करने के बजाय, केंद्र सरकार ने बीएनएस, 2023 में 'राजद्रोह' को एक अपराध के रूप में फिर से पेश किया है, यद्यपि एक अलग परिभाषित नाम के तहत!!

सीजेपी विशेष रूप से बीएनएस की धारा 152 को उजागर करना चाहता है, जिसमें कहा गया है कि "ऐसे कार्य जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को ख़तरे में डाल रहे हैं, जानबूझकर या जानबूझकर, शब्दों द्वारा, या तो बोले गए या लिखित, या विज्ञान द्वारा, या दृश्यमान प्रतिनिधित्व द्वारा, या इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा या वित्तीय साधनों के उपयोग से या अन्यथा, समाप्ति या सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को उत्तेजित या उत्तेजित करने का प्रयास करता है, या अलगाववादी गतिविधियों की भावना को प्रोत्साहित करता है, या भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को ख़तरे में डालता है' या ऐसे किसी भी कार्य में लिप्त होता है या करता है, उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी या कारावास की सजा हो सकता है जो बढ़ सकता है 7 साल तक, और जुर्माना भी लगाया जाएगा।" अपने आप में अस्पष्ट और व्यापक होने के बावजूद, एमएसपीएस विधेयक 2024, उक्त प्रावधान के लिए एक अविश्वसनीय समानता भी रखता है।

इसके अतिरिक्त, बीएनएस, 2023 की धारा 113 (1), जो अपने दायरे में किसी भी व्यक्ति को कवर करती है जो भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा को ख़तरे में डालने या धमकी देने की संभावना के इरादे से कोई भी कार्य करता है या भारत या किसी भी विदेशी देश में लोगों या लोगों के किसी भी वर्ग में आतंक पर हमला करने की संभावना है, यूएपीए, 1961 की धारा 15 को दर्शाता है। एकमात्र अंतर यह है कि यह एक विदेशी देश में भी किए गए कृत्यों से संबंधित है।

इसी तरह, धारा 113 (2) जो इस तरह के आतंकवादी कृत्य करने से संबंधित है जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु होती है या अन्यथा, यूएपीए की धारा 16 को शब्दशः दर्शाती है। धारा 113 (3), जो उन लोगों को कवर करती है जो साजिश करते हैं या करने का प्रयास करते हैं, या वकालत करते हैं, उकसाते हैं, सलाह देते हैं या उकसाते हैं, सीधे या जानबूझकर आतंकवादी कृत्य के कमीशन की सुविधा प्रदान करते हैं या आतंकवादी अधिनियम के कमीशन के

लिए किसी भी कार्य की तैयारी करते हैं, यूएपीए की धारा 18 को शब्दशः दर्शाता है। धारा 113 (4), जो उन लोगों से संबंधित है जो आतंकवादी अधिनियम में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किसी भी शिविर या शिविर को व्यवस्थित करते हैं या आयोजित करने का कारण बनते हैं, यूएपीए की धारा 18ए शब्दशः को दर्शाता है। धारा 113 (5) में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी संगठन का सदस्य है जो आतंकवादी कृत्य में शामिल है, यूएपीए की धारा 20 को शब्दशः दर्शाता है।

धारा 113 (6), जो स्वेच्छा से आश्रय देने या ऐसे व्यक्ति को छिपाने के अपराध को कवर करती है जो एक आतंकवादी करता है, को यूएपीए शब्दशः की धारा 19 से लिया गया है।

धारा 113 (7), जो किसी भी आतंकवादी कृत्य के कमीशन से प्राप्त या प्राप्त किसी भी संपत्ति को जानबूझकर रखने के अपराध को अपराधीकृत करती है, को यूएपीए की धारा 21 से लिया गया है, जो बीएनएस में व्यापक दायरे के साथ मौजूद है।

वर्तमान क़ानूनी परिदृश्य के प्रकाश में, एमएसपीपी विधेयक 2024 यूएपीए 1961 और पीएमएलए, 2002 जैसे क़ानूनों के तहत पहले से ही कठोर उपायों के अनावश्यक और ख़तरनाक विस्तार का प्रतिनिधित्व करता है। महाराष्ट्र के आपराधिक क़ानूनों में ऐसे कड़े प्रावधानों को शामिल करना, विशेष रूप से आवश्यक सुरक्षा उपायों के बिना, दुरुपयोग की संभावना के बारे में गंभीर चिंता पैदा करता है। सरकारी नीतियों, सत्ता में व्यक्तियों आदि के लिए किसी भी राजनीतिक या रचनात्मक विरोध के असहिष्णुता के वर्तमान माहौल और जांच एजेंसियों द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को देखते हुए, यह विधेयक केवल मनमाने ढंग से राज्य कार्रवाई के जोखिम को गहरा करता है और आगे मौलिक अधिकारों को ख़तरा देता है। सवाल बना हुआ है:

एक और क़ानून क्यों बनाएं जो केवल भय और दमन के माहौल को मज़बूत करने का काम करता है, इसके बजाय...
क़ानून प्रभारों की बहुलता द्वारा उत्पीड़न

एक और ख़तरनाक निहितार्थ जो एक और कठोर राज्य क़ानून को लागू करने के इस प्रयास के साथ होगा, वह है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत वैधानिक ज़मानत मांगने वाले विचाराधीन क़ैदियों के प्रावधान पर इसका प्रभाव। बीएनएसएस की धारा 479 में वैधानिक ज़मानत के लिए बहुत सख़्त ज़मानत प्रावधान हैं। उक्त खंड परीक्षणों के तहत वैधानिक ज़मानत देने की शर्तों को सीमित करता है - नए क़ानून में एक खंड है जो कार्प्स की धारा 436 ए से मेल खाता है, हिरासत में एक विशेष अवधि बिताने के बाद परीक्षण के बाद वैधानिक ज़मानत देने की प्रक्रिया को अपनाने के लिए प्रदान करता है। पुराने सीआरपीसी में, यदि एक परीक्षण के तहत ने निरोध में एक अपराध के लिए कारावास की अधिकतम अवधि का आधा खर्च किया है, तो उन्हें व्यक्तिगत बांड पर रिहा किया जाना चाहिए (उन अपराधों पर लागू नहीं किया जाना चाहिए जो मृत्यु से दंडनीय हैं) बीएनएसएस, 2023 उक्त प्रावधान को बरकरार रखता है, और इसे और सख़्त बनाता है।

हालांकि, अब, धारा 479 के तहत, निचली सुनवाई वाले क़ैदियों को ज़मानत देने का प्रावधान अब उन लोगों तक सीमित होगा जो मुकदमे के तहत पहली बार अपराधी हैं यदि उन्होंने अधिकतम सजा का एक तिहाई पूरा कर लिया है। चूंकि आरोप पत्र अक्सर कई अपराधों का उल्लेख करते हैं, यह अनिवार्य ज़मानत के लिए कई परीक्षणों के तहत अयोग्य बना सकता है। इसके अलावा, उक्त प्रावधान के माध्यम से, उक्त धारा के तहत ज़मानत प्राप्त करने के निषेध को उन अपराधों तक भी विस्तारित किया गया है जो आजीवन कारावास से दंडनीय हैं। इसलिए, निम्नलिखित परीक्षण के तहत उक्त धारा के तहत वैधानिक ज़मानत के लिए आवेदन करने से रोक दिया गया है

यदि: आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध, और ऐसे व्यक्ति जिनके पास एक से अधिक अपराधों में कार्यवाही लंबित है।

एमएसपीबी विधेयक 2024 की शुरूआत, जब बीएनएसएस 2023 और यूएपीए 1961 जैसे मौजूदा क़ानूनों के साथ संयुक्त होती है, तो विशेष रूप से वैधानिक ज़मानत तक पहुंच के संदर्भ में, विचाराधीन लोगों के अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण ख़तरा है। बीएनएसएस 2023 की धारा 479 के तहत, पहले से ही सख़्त ज़मानत प्रावधानों को और भी अधिक प्रतिबंधात्मक बना दिया गया है, पहली बार अपराधियों को ज़मानत प्राप्त करने से रोक दिया गया है जब तक कि उन्होंने अपनी सजा का एक तिहाई नहीं दिया है। एमएसपीपी बिल 2024 के तहत आरोपी लोगों के लिए, यूएपीए 1961 या बीएनएसएस 2023 जैसे अन्य क़ानूनों के संयोजन में, इसके परिणामस्वरूप व्यक्तियों को विस्तारित अवधि के लिए ज़मानत से वंचित किया जा सकता है, भले ही वे अंततः निर्दोष पाए जाएं। आरोपों के साथ अक्सर कई अपराधों को शामिल करते हुए, जिसमें आजीवन कारावास से दंडनीय भी शामिल है, विचाराधीन क़ैदी खुद को अनिवार्य ज़मानत के लिए अयोग्य पा सकते हैं। इसका प्रभाव विनाशकारी हो सकता है, क्योंकि निर्दोष व्यक्तियों को वर्षों तक हिरासत में रहने के लिए मजबूर किया जा सकता है, इन क़ानूनों के तहत राज्य को दी गई भारी शक्ति के कारण उनके लंबे समय तक कारावास को चुनौती देने में असमर्थ। यह क़ानूनी प्रणाली की निष्पक्षता और बिना मुकदमे के व्यक्तियों की अनिश्चितकालीन हिरासत की संभावना के बारे में गंभीर चिंताओं को उठाता है, जो न्याय के सिद्धांत को और कम करता है।

यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि यूएपीए में 2019 के संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिकाएं, विशेष रूप से धारा 35 और 36, जो सरकार को व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित करने और उन्हें अनुसूची IV में शामिल करने के लिए व्यापक शक्तियां प्रदान करती हैं, लंबित हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों को पहले उनकी सुनवाई करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि इस तरह की लेबलिंग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगी।

हमारा संविधान, हमारे क़ानून

लगातार सरकारों के दावों के बावजूद कि ग़ैरक़ानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए ऐसे क़ानून आवश्यक हैं, इतिहास ने अन्यथा दिखाया है। व्यवहार में, इस तरह के कठोर क़ानूनों का व्यापक रूप से दुरुपयोग किया गया है, जैसा कि पत्रकारों और मानवाधिकार संगठनों द्वारा बड़े पैमाने पर प्रलेखित किया गया है। छत्तीसगढ़ विशेश जन सुरक्षा अधिनियम (2005) और आंध्र प्रदेश विशेष सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (1992) स्पष्ट उदाहरणों के रूप में कार्य करते हैं, जिनका उपयोग पत्रकारों, वकीलों, पर्यावरण रक्षकों, नागरिक कार्यकर्ताओं और आदिवासी प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ केवल असंतोष के संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार का उपयोग करने के लिए किया गया है। छत्तीसगढ़ अधिनियम को संवैधानिक चुनौती वर्तमान में माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है। इस ख़तरनाक मिसाल को देखते हुए, हम इस बात से चिंतित हैं कि महाराष्ट्र में इसी तरह के दमनकारी क़ानून का उपयोग वास्तविक सुरक्षा ख़तरों को दूर करने के लिए नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके बजाय राज्य के गतिशील सामाजिक और राजनीतिक जीवन को रोकने के लिए अपने स्वयं के नागरिकों को लक्षित करने के लिए किया जाएगा।

महाराष्ट्र हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक सुधार का एक मशाल वाहक रहा है, इसके लोगों ने भारत के राजनीतिक और संवैधानिक इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि, यह विधेयक भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों, विशेष रूप से भाग III के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का सीधे खंडन करता

है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19(1) (ए)), शांतिपूर्ण सभा का अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(बी)), और संघ बनाने का अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(सी)) एक कार्यशील लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। इन अधिकारों पर कोई भी प्रतिबंध अनुच्छेद 19(2) के तहत तर्कसंगतता की परीक्षा को पूरा करना चाहिए और मनमाना, अत्यधिक या अनुपातहीन नहीं होना चाहिए। इस विधेयक के अस्पष्ट और व्यापक प्रावधान इस संवैधानिक मानक को पूरा करने में विफल रहते हैं और अनियंत्रित राज्य दमन के द्वार खोलते हैं।

इसके अलावा, इस विधेयक के दुरुपयोग की संभावना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उचित प्रक्रिया के उल्लंघन के बारे में चिंताओं को बढ़ाती है। असहमति को अपराधी बनाकर और वैध राजनीतिक और सामाजिक सक्रियता के दमन को सक्षम करके, विधेयक न केवल महाराष्ट्र के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कमजोर करता है बल्कि लोकतांत्रिक शासन के क्षरण के लिए एक ख़तरनाक मिसाल भी स्थापित करता है।

निष्कर्ष में, हम दृढ़ता से मानते हैं कि महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, 2024, असंवैधानिक, अत्यधिक व्यापक, मनमाना है, और इस तरह से डिज़ाइन किया गया है जो दुरुपयोग को आमंत्रित करता है। हम आपकी चयन समिति से आग्रह करते हैं कि इन चिंताओं को अधिक विस्तार से प्रस्तुत करने के लिए हमें व्यक्तिगत सुनवाई प्रदान करें। इसके अलावा, हम आपसे और समिति के सदस्यों से इस विधेयक को पूरी तरह से अस्वीकार करने का आह्वान करते हैं, जिससे महाराष्ट्र की गौरवशाली लोकतांत्रिक परंपराओं को क़ायम रखा जा सके और इसके लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जा सके।

सादर,

नंदन मालुस्ते
अध्यक्ष, सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस, मुंबई.

तिस्ता सेतलवाड
सचिव, सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस, मुंबई.